गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 106
दि. 14.08.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

भारत की राष्ट्रपति कल 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 79 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल (14 अगस्त, 2025) को राष्ट्र को संबोधित करेंगी।

यह संबोधन 1900 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा।

श्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 'आज #HarGharTiranga अभियान के अंतर्गत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं।'

आईसीआईसीआई ने ग्राहकों के विरोध के बाद वापस लिया 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने का नियम

आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका देते हुए सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये कर दिया था। लेकिन अब बैंक अपने इस फैसले को लेकर बैकफुट पर आ चुका है। बैंक ने न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि की शर्तों में बदलाव किया है। बैंक ने अब इस राशि को ₹50,000 से घटाकर ₹15,000 कर दिया है। बैंक ने ये फैसला ग्राहकों की प्रतिक्रिया के बाद लिया है। बैंक का अपना फैसला बदलने का उद्देश्य ग्राहकों की अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को पूरा करना है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट आईसीआईसीआई बैंक ने पहले ₹50,000 का न्यूनतम एमएबी प्रस्तावित किया था, लेकिन अब इसे घटा दिया है।

राज ठाकरे की एमएनएस ने निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया दिवाली के बाद शुरू होने की उम्मीद है। चंद दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने यह जानकारी दी थी। जिसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने आगामी निकाय चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की विपक्षी दलों की मांग का समर्थन किया है। राज ठाकरे की मनसे के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और अपनी मांगों की सूची सौंपी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) के उपयोग पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे

एक भव्य आयोजन समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत की झलक पेश करेगा

(जीएनएस)।

राष्ट्र 15 अगस्त 2025 को अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री इस प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएँगे और संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय "नया भारत" रखा गया है। यह समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत के लगातार विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने के एक मंच के तौर पर काम करेगा।

समारोह लाल किले पर आगमन के साथ, प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह करेंगे। रक्षा सचिव, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का प्रधानमंत्री से परिचय कराएँगे। इसके बाद, दिल्ली क्षेत्र के जीओसी, श्री नरेंद्र मोदी को सलामी मंच तक ले जाएँगे, जहाँ अंतर-सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड की संयुक्त टुकड़ी, प्रधानमंत्री को सलामी देगी। इसके बाद, प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।

प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में 96 जवान शामिल होंगे (एक अधिकारी और सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस, प्रत्येक से 24 जवान।

भारतीय वायु सेना इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का समन्वय कर रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर ए एस सेखों संभालेंगे।

प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना दस्ते की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह और वायु सेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभालेंगे। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान अतिरिक्त डीसीपी श्री रोहित राजबीर सिंह के हाथ में होगी।

मुख्यमंत्री ने 'हर घर तिरंगा अभियान' का शुभारम्भ किया

प्रधानमंत्री जी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत विजन से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमें विकसित व आत्मनिर्भर उ0प्र0 के विजन को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा : मुख्यमंत्री

तिरंगा यात्रा हमें भारत माता, भारतीय महापुरुषों व वीर क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करती

देश व प्रदेश के प्रत्येक घर में भारत की आन-बान-शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाना चाहिए

लखनऊ : 13 अगस्त, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत विजन से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमें विकसित व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर 'हर घर तिरंगा अभियान' (13 से 15 अगस्त, 2025) का शुभारम्भ करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज 'हर घर तिरंगा अभियान' का शुभारम्भ किया जा रहा है। हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है। आजादी के अमृतकाल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, महान क्रान्तिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमें भारत माता, भारतीय महापुरुषों व वीर क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करती है। देश व प्रदेश के प्रत्येक घर में भारत की आन-बान-शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाना चाहिए।

सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

(जीएनएस)।

सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री एवं व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री श्री गान किम योंग के नेतृत्व में सिंगापुर के एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज (13 अगस्त, 2025) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। यह प्रतिनिधिमंडल भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) की तीसरी बैठक के लिए दिल्ली में है।

राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक परिवेश में भी, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी फल-फूल रही है। उन्होंने इस वर्ष के आरंभ में, हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर, राष्ट्रपति श्री थर्मन षणमुगरत्नम की राजकीय यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि आईएसएमआर सहित उच्चतम स्तरों पर इस तरह की नियमित बातचीत हमारे बहुआयामी संबंधों को निरंतर गति प्रदान करेगी।

राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ सिंगापुर के मजबूत रुख की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और हिंद-प्रशांत विजन में एक प्रमुख साझेदार है। व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्रों में हमारी मजबूत साझेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि यह साझेदारी अब कौशल विकास, हरित अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के उभरते क्षेत्रों में भी विस्तारित हो रही है।

दिल्ली-एनसीआर स्ट्रे डॉग्स रिमूवल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टकराव, अब सीजेआई बोले- 'गौर करूंगा'

(जीएनएस)।

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है-और इस बार, इसकी गूंज सीधे देश के सबसे बड़े जज के दरबार तक जा पहुंची है। बुधवार, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई मानो किसी कानूनी रोमांचक कथा का हिस्सा थी।

एक ओर था सालों पुराना फैसला, जिसने समुदाय के कुत्तों को अंधाधुंध मारने पर सख्त रोक लगाकर पशु-प्रेमियों को राहत दी थी, और दूसरी ओर था ताजा आदेश, जिसमें दिल्ली-एनसीआर की हर गली, मोहल्ले और सड़क से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सख्त निर्देश जारी किया गया था।

जब अदालत में वकील ने दो अलग-अलग पीठों के इन परस्पर विरोधी आदेशों की ओर इशारा किया, तो माहौल गंभीर हो गया। बहस के बीच, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने ध्यानपूर्वक सुना और कुछ क्षणों के मौन के बाद एक वाक्य कहा, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया-"मैं इस पर गौर करूंगा।"

11 अगस्त को क्या आया आदेश?

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों, खासकर बच्चों पर हमलों की "बेहद गंभीर" स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-एनसीआर की सभी सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर में भेजा जाए।

अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह 6 से 8 हफ्तों में लगभग 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए और भविष्य में क्षमता बढ़ाने की योजना भी तैयार करे।

नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद

जेपी सेनानियों के सम्मान में ऐतिहासिक निर्णय, पेंशन दोगुनी, 1 अगस्त 2025 से लागू- सम्राट चौधरी

(जीएनएस)।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सालों तक संघर्ष करने वाले जेपी आंदोलन के सेनानियों के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। बिहार कैबिनेट ने उनके सम्मान पेंशन को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर न केवल एक आर्थिक राहत दी है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया है।

समाज के असली नायकों का सम्मान केवल भाषणों में नहीं, बल्कि ठोस कदमों से होना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक चले आंदोलन में मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे सेनानियों को अब पहले से दोगुना पेंशन मिलेगा।

1 माह से 6 माह तक जेल में रहने वालों की पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और 6 माह से अधिक जेल में रहने वालों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, और पेंशनधारी के निधन के बाद उनके जीवित पति/पत्नी को भी इसी दर से पेंशन मिलेगी।

यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता भर नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी के त्याग को स्मरण करने का अवसर है, जिसने लोकतंत्र बचाने के लिए अपने जीवन के सुनहरे वर्ष जेल में गुजार दिए। ऐसे में एनडीए सरकार का यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि देश और राज्य के लिए किया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जाता।

राजनीति में बहुत बार घोषणाएं होती हैं, पर जब कोई सरकार पुराने संघर्षों के योद्धाओं को याद कर उन्हें उचित सम्मान देती है, तो यह उस शासन के संवेदनशील और जिम्मेदार चरित्र को दशार्ता है। जेपी सेनानियों के सम्मान में उठाया गया यह कदम बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल संसद और विधानसभाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में है, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और कीमत चुकाई।

पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमारा ही होगा : श्री शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा-रायसेन में तिरंगा यात्रा - स्वदेशी मार्च निकाला, स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन

हमारा मान तिरंगा, हमारी शान तिरंगा, हमारा अभिमान तिरंगा : केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान

बहनें अब लखपति दीदी के साथ मिलेनियर दीदी भी बनेंगी : श्री शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने लोगों से स्वदेशी अपनाने का आ'ान किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा-रायसेन में तिरंगा यात्रा व स्वदेशी मार्च निकाला। वहीं श्री शिवराज सिंह ने यात्रा से पहले विदिशा में स्वयं-सहायता समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन भी मनाया। तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च विदिशा के माधवगंज चौराहे से प्रारंभ होकर रायसेन के महामाया चौक पर समाप्त हुई। श्री शिवराज सिंह ने भी आम जनता से स्वतंत्रता दिवस पर अपने-अपने घरों पर झंडा फहराने की अपील की और स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रध्वज देश का गौरव और सम्मान है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और अब फिर स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमारा राष्ट्रीय पर्व... बहनों और भाइयों अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घर भी तिरंगा फहराएं।

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में स्वयं-सहायता समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया और देश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने कहा कि आज बहनों ने राखी मेरी कलाई पर बांधी है, जो प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का धागा है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि लखपति दीदी अभियान चल रहा है।

मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, उसमें से 2 करोड़ के आसपास तो लखपति दीदी बनने ही वाली हैं, और समय से पहले हम 3 करोड़ दीदीयों को लखपति दीदी बना देंगे। और जो लखपति दीदी बन गई हैं, उन्हें मिलेनियर दीदी बनाएंगे। मिलेनियर दीदी का मतलब है, जिसकी आमदनी 10 लाख है, इस संकल्प को भी पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विराट संकल्प को साकार करने और बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा यात्रा, स्वदेशी मार्च और स्वयं-सहायता समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में बहनों और आमजन को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया।

इस दौरान श्री शिवराज सिंह ने कहा कि, हम सभी ये संकल्प लेंगे कि हम जो भी चीज, जिसकी जरूरत हमारी ज़िंदगी में है, वो अपने देश में ही बनी खरीदेंगे। या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में बनी हुई चीजें ही खरीदें। हम विदेशी नहीं खरीदेंगे ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने का आ'ान किया है। उन्होंने कहा कि मैं, और आप भी अपने घर में जो भी चीज आएगी चाहे वो खाने की हो, पहनने की, तेल, साबुन, शैम्पू, कुछ भी चीज हो। हम अपने देश में बनी चीज ही खरीदेंगे। श्री चौहान ने संकल्प दिलाते हुए कहा कि, मैं कहूँगा आप दोहराना.. मैं संकल्प लेता हूँ कि, अपने जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएँ, अपने देश में बनी ही खरीदूँगा। आस-पास और परिवार और गाँव में सभी को अपने देश में बनी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करूँगा।

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि, हमारा मान तिरंगा, हमारी शान तिरंगा, हमारा अभिमान तिरंगा। झण्डा ऊँचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये उद्घोष करते हुए लाखों क्रांतिकारी हँसते-हँसते शहीद हो गए। अंग्रेजों ने ये आजादी चाँदी की तस्तरी में रखकर भेंट नहीं की है। हजारों क्रांतिकारी साथी हँसते-हँसते फाँसी के फंदों पर झूल गए थे।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

भारत को मुनीर की खुली धमकी

अमेरिकन सिटी फ्लोरिडा से पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी भरा बयान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष के तीन महीने बाद अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। मुनीर ने दावा किया है कि मई में हुए संघर्ष में पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने का दावा करता है लेकिन ऐसा वुछ नहीं है। आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब शनिवार और रविवार को ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय थल सेना और वायु सेना प्रमुखों के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। पहले बता दें कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले के जवाब में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर किसी भी पारंपरिक मिशन से अलग था। शनिवार को भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दावा किया था कि मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत ने छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। हालांकि उसी रोज पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान जारी कर इसका खंडन किया। 10 मई को संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद गोलीबारी थम गई थी। उस समय पाकिस्तान ने भारत के पांच लड़ावू विमान गिराने का दावा किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। फ्लोरिडा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक निजी कार्यक्रम में दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के भेदभाव पूर्ण और दोहरे व्यवहार वाली नीतियों के खिलाफ एक सफल वूटनीतिक युद्ध लड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में शामिल है और इस संबंध में उन्होंने कनाडा में एक सिख नेता की हत्या, कतर में आठ नौसेना अधिकारियों का मामला और वुलभूषण जाधव जैसी घटनाओं का उदाहरण दिया। गौरतलब है कि भारत पहले ही इन सभी आरोपों का खंडन कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद आभारी है। जिनके राजनीतिक नेतृत्व में न केवल भारत पाक युद्ध को रोका बल्कि दुनिया में कई युद्धों को भी रोका। फील्ड मार्शल मुनीर ने अपने भाषण में कश्मीर को एक अधूरा एजेंडा बताया।

आसिम मुनीर यहीं नहीं रूके उन्होंने भारत को खुली धमकी दे डाली।

मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो हम मिसाइल से उसे उड़ा देंगे। मुनीर ने कहा, हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो हम मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर यह गीदड़ भभकी देने से भी नहीं चूके कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर का यह बयान इस लिहाज से सनसनीखेज है कि पहली बार अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जिस तरह खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस पर अपनी-अपनी राय हो सकती है। बहरहाल इससे एक बात तो साबित होती ही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति होना केवल भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यह दुखद है कि मुनीर का यह बयान अमेरिका की धरती से आया है। यह पहली बार है जब किसी ने अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश के लिए इस तरह के धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह भी पहली बार है जब किसी सेना प्रमुख ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। मुनीर के बयान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने सही जवाब दिया है कि जिस देश में सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हो, वहां परमाणु कमांड और वंट्रोल की विश्वसनीयता पर संदेह होना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा।

गुजरात को मिली एक और पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कॉलेज की सौगात

कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिम्मतनगर में कामधेनु वेटरनरी कॉलेज को मिली स्वीकृति, 80 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

23 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक कैम्पस, उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ ही विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध

तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए

गांधीनगर, 13 अगस्त : गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा और अंतिम छोर के लोगों की सुख-समृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, राज्य के विद्यार्थियों के उज्ज्वल करियर के लिए एक और नई सुविधा की सौगात दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के हिम्मतनगर में एक नया पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से 80 सीटों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिम्मतनगर में नया कामधेनु वेटरनरी कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा

गया था। इस विषय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) द्वारा निरीक्षण और उचित समीक्षा के बाद इस वर्ष से यह कॉलेज शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

कॉलेज प्रवेश और पाठ्यक्रम

वेटरनरी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए आणंद, नवसारी, जूनागढ़ और दांतीवाड़ा के बाद यह राज्य में पांचवां कॉलेज है। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद इस कॉलेज में नीट की परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी इस कॉलेज में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस (बीवीएससी) और एनिमल हसबेंडरी (एएच) डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जिसमें 01 प्रिंसिपल, 04 प्रोफेसर, 07 एसोसिएट प्रोफेसर, 34 असिस्टेंट प्रोफेसर और 23 गैर-शिक्षण स्टाफ शामिल हैं।

अत्याधुनिक कैम्पस और कम फीस पर उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधा

इस कॉलेज के शुरू होने से अब राज्य के विद्यार्थियों को एक और बेहतर कॉलेज में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस कॉलेज का कैम्पस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। विद्यार्थियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार कम फीस पर उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ ही आवास की सुविधा भी उपलब्ध है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में पशु स्वास्थ्य मेलों की शुरूआत की गई थी। गुजरात देश का ऐसा राज्य है; जहाँ पशुधन के लिए हेल्थकार्ड, पशु स्वास्थ्य मेलों तथा पशुओं के मोतियाविंद के ऑपरेशन की सुविधाएँ भी विकसित की गई हैं। इस अभियान को आगे ले जाने में यह कॉलेज आगामी समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गुजरात : 22 बड़ी इकाइयों के आवेदन मंजूर, अनुमानित 4136 से अधिक रोजगार का सृजन

राज्य में कुल 1478 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश वाली 22 बड़ी इकाइयों के आवेदन मंजूर, अनुमानित 4136 से अधिक रोजगार का सृजन

राज्य में 'इंसेंटिव टु इंडस्ट्रीज' योजना अंतर्गत अनुमानित 1.48 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ 1.65 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन : उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत

गांधीनगर, 13 अगस्त : गांधीनगर में उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत की अध्यक्षता में उद्योगों को फाइनल एलिजिबिलिटी प्रमाणपत्र देने संबंधी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 1478.71 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश वाली 22 बड़ी इकाइयों के आवेदन मंजूर किए गए, जिससे राज्य में अनुमानित 4136 नए रोजगार का सृजन हुआ है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सहित समग्र देश में एक उद्योगानुकूल इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है, जिससे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में 'इंसेंटिव टु इंडस्ट्रीज' योजना अंतर्गत 148336.35 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 1.65 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है, जिसके फलस्वरूप एमएसएमई सेक्टर के लघु एवं मध्यम स्तरीय आनुषांगिक उद्योगों को अधिक वेग मिला है।

श्री राजपूत ने आगे कहा कि आज मंजूर किए गए आवेदनों में अहमदाबाद जिले में मेटल, पेपर,

फूड-एग्रो, सिमेंट-कंक्रीट सेक्टर में 383.91 करोड़ रुपए, कच्छ में मेटल सेक्टर में 227.77 करोड़ रुपए, भरूच में केमिकल एवं सिरामिक सेक्टर में 218.88 करोड़ रुपए, मेहसाणा में पेपर सेक्टर में 55.23 करोड़ रुपए, मोरबी में सिरामिक, मेटल, पेपर, टेक्सटाइल सेक्टर में 167.70 करोड़ रुपए, राजकोट में मेटल सेक्टर में 36.22 करोड़ रुपए, वलसाड में केमिकल, प्लास्टिक तथा पेपर सेक्टर में 359.47 करोड़ रुपए तथा सुरेन्द्रनगर जिले में पेपर सेक्टर में 29.53 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जो राज्य में उद्योगों को अधिकाधिक सक्षम बनाने तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से गुजरात में रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि गुजरात को व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रकाशस्तंभ बनाने के विजन के साथ राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2015 अंतर्गत 'इंसेंटिव टु इंडस्ट्रीज' योजना लागू की गई है। गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में अग्रसर करने, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने तथा नए प्रोजेक्ट्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ यह योजना लागू की गई है। राज्य में आने वाले उद्योगों को नेट एसजीएसटी सहायता देने संबंधी इस योजना के माध्यम से गुजरात केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में निवेश का सबसे आकर्षक स्थल बना है, जिसे बड़े उद्योगों द्वारा अच्छा-खासा समर्थन मिला है।

इस बैठक में उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप सहित उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

पीएनबी ने उन्नत डीलर वित्तपोषण समाधानों के लिए मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की

13 अगस्त 2025: भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत समस्त भारत में मारुति सुजुकी के डीलर नेटवर्क के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग समाधान प्रदान किए जाएँगे। यह रणनीतिक साझेदारी देश भर के ऑटोमोबाइल डीलरों की वर्किंग कैपिटल तक पहुँच बढ़ाने और उनकी परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किए गए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद प्रदान करेगी।

पीएनबी डिजिटल माध्यम से ₹25 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं हेतु स्वीकृति प्रदान कर रहा है। यह साझेदारी मारुति सुजुकी इंडिया

लिमिटेड के डीलरों को बिना किसी परेशानी के ऋण सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को सीएमएस (नकद प्रबंधन प्रणाली) सेवाएँ भी प्रदान करेगी।

इस समझौता ज्ञापन पर पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र, वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी, मार्केटिंग एवं सेल्स श्री पार्थो बनर्जी, कार्यपालक उपाध्यक्ष, मार्केटिंग एवं सेल्स श्री त्सुयोशी ताकेशिता और मारुति सुजुकी फाइनेंस एवं ड्राइविंग स्कूल के उपाध्यक्ष श्री विशाल शर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस साझेदारी पर अपने व्याख्यान में, पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने कहा कि "मारुति सुजुकी के साथ यह साझेदारी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों के माध्यम से भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पीएनबी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारे विशेष रूप से तैयार किए गए इन्वेंट्री फंडिंग उत्पाद डीलरों को बेहतर तरलता, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और त्वरित अनुमोदन तंत्र प्रदान करेंगे। हमें विश्वास है कि यह सहयोग ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और साथ ही मोबिलिटी क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार के रूप में पीएनबी की स्थिति को और सशक्त करेगा। यह साझेदारी रणनीतिक उद्योग सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।"

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी, मार्केटिंग एवं सेल्स, श्री पार्थो बनर्जी ने कहा, "हमारे डीलर पार्टनर हमारी सफलता के अभिन्न अंग हैं। पंजाब नैशनल बैंक के साथ यह साझेदारी बढ़ती बाजार माँगों को पूरा करने के लिए मजबूत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम आगे है। हमारा मानना है कि यह पहल उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी और समग्र ग्राहक संतुष्टि में योगदान देगी। यह साझेदारी ऑटोमोटिव इकोसिस्टम को समर्थन देने और भारत के मोबिलिटी सेक्टर के विकास में योगदान देने के मारुति सुजुकी और पंजाब नैशनल बैंक के साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है।"

इनमोबी ने लखनऊ में किया प्रवेश; विश्वस्तरीय बाजारों के लिए डीप-टेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए खोला नया कार्यालय

लखनऊ का नया कार्यालय जनरेटिव एआई, एमएलओ पीएस, ऑटोमेशन एवं एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक तकनीकों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर भारत में टेक हब की भूमिका निभाएगा।

यह पहल उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो लखनऊ को उभरते एआई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करेगा।

लखनऊ, 13 अगस्त, 2025: एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर InMOBI ने आज लखनऊ में नए टेक्नोलॉजी सेंटर का लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ यह शहर कंपनी के ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क में शामिल हो गया है।

InMOBI, जो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में मशहूर है, लखनऊ में प्रवेश करने वाली कुछ पहली ग्लोबल डीप-टेक कंपनियों में से एक है। यह InMOBI के मिशन के अनुसार भारत के महानगरों के दायरे से बढ़कर छोटे शहरों में इनोवेशन को विकेंद्रीकृत करने, प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा एआई एवं डीप-टेक में भारत के ग्लोबल लीडरशिप को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ का यह टेक सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग ऑपरेशन्स, ऑटोमेशन और बड़े पैमाने पर एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास सहित आधुनिक तकनीकों में इनोवेशन्स को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाएगा।

InMOBI ने आने वाले सालों में इस सेंटर में 500 डीप-टेक इंजीनियर, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट और डेटा साइंस प्रोफेशनल्स भर्ती करने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि इस निवेश से क्षेत्र में 3000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी- जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश को 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की

मानसिकता, महत्वाकांक्षा एवं अवसर से प्रेरित होती है,' मोहित सक्सेना, सह-संस्थापक एवं ग्रुप सीटीओ InMOBI और ग्लांस ने कहा। "पिछले दो दशकों में हमने बैंगलोर और सैन फ्रांसिस्को (दो विश्वस्तर पर विख्यात टेक हब) के बाहर विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग टीमें बनाई हैं। अब हम लखनऊ को भी इस लीग में शामिल कर रहे हैं। यह पारम्परिक महानगरों के दायरे से बढ़कर वाइब्रेन्ट डीप-टेक सिस्टम बनाने की दिशा में एक नई शुरूआत है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय प्रतिभा में निवेश, अकादमिक जगत के सहयोग और विश्वस्तरीय बाजारों के लिए आधुनिक उत्पादों के निर्माण के साथ हम भारत के इनोवेशन मानचित्र को नया आकार दे रहे हैं- यह केवल एक शुरूआत है।' सक्सेना ने कहा।

लखनऊ में भारत की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रतिभा है । कई प्रतिष्ठित संस्थान इसी क्षेत्र के आस-पास हैं, जैसे - आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी लखनऊ, आईआईएम लखनऊ और एमएनएनआईटी अलाहाबाद। ऐसे में यह क्षेत्र फ्यूचर-रैडी टेक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हब है। InMOBI में व्यवहारिक प्रोडक्ट प्रशिक्षण प्रदान करने तथा वास्तविक दुनिया की जरूरतों के अनुरूप इंटर्नशिप एवं अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए स्थानीय यूनिवर्सिटियों एवं शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी की योजना बनाई है । इन प्रयासों से अकादमिक जगत एवं इनोवेशन के बीच के अंतर को दूर करने में मदद मिलेगी।

'लखनऊ में हमारी मौजूदगी इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रतिभा हर स्थान पर मौजूद है- हमारी जिम्मेदारी इसे सही दिशा प्रदान करना है, शेफाली राय, चीफ 'मन रिसोर्सेज ऑफिसर, InMOBI और ग्लांस ने कहा। हमारा उद्देश्य ऐसे कार्यस्थल का निर्माण करना है जहां लोगों को आधुनिक विश्वस्तरीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए अपना शहर न छोड़ना पडे। क्लटडइक के बेहतरीन परफोर्मेन्स, समावेशी मूल्यों एवं डीप-टेक अवसरों के साथ हम उभरती प्रतिभा को उनके अपने क्षेत्र में विश्वस्तरीय करियर बनाने के लिए तैयार करना चाहते हैं।'

InMOBI का नया लखनऊ कार्यालय कंपनी की इनोवेशन योजनाओं तथा इसी साल एआई के लिए की गई 200 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता का एक भाग है, जिसमें ग्लांस एआई का लॉन्च भी शामिल है। ग्लांस एआई एक रेवोल्युशनरी एआई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में खरीददारी के तरीके को बदल रहा है। अपने आर एण्ड डी फुटप्रिंट को विकेंद्रीकृत करके कंपनी पारम्परिक शहरी केन्द्रों के दायरे से बढ़कर इनोवेशन, प्रतिभा के समावेशी विकास एवं स्थायी टेक सिस्टम के विकास को बढ़ावा देना चाहती है।

ट्राई ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई की 17.02.2025 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के 03.07.2025 के बैक-रेफरेंस का जवाब दिया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई की 17.02.2025 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।

इससे पहले, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत दिनांक 26.07.2024 के एक संदर्भ के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण के लिए शुल्क या प्रभार सहित नियम और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, दिनांक 17.10.2024 के एक अधिशेष पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 3(1)(बी) के तहत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण पर विचार करने का अनुरोध किया था।

हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, ट्राई ने 17.02.2025 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर सिफारिशें दूरसंचार विभाग को प्रदान कीं।

इसके बाद, 03.07.2025 को, दूरसंचार विभाग ने ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के तहत एक बैक-रेफरेंस भेजा और ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर कुछ सिफारिशों के संबंध में पुनर्विचारित सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया, जहां सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या उनमें संशोधन की आवश्यकता है।

ट्राई की सिफारिशों पर सरकार के प्रथम दृष्टया विचारों का विश्लेषण करने के बाद, ट्राई ने दूरसंचार विभाग को बैक-रेफरेंस पर अपना जवाब भेज दिया है। बैक-रेफरेंस पर ट्राई का जवाब ट्राई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण या विवरण के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

नेटवर्क योजना समूह की 98वीं बैठक में रेलवे, सड़क, लॉजिस्टिक्स और वस्त्र क्षेत्र की 7 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया गया

(जीएनएस)।

नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक सड़क/राजमार्ग परियोजना, एक मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी), तीन रेल परियोजनाएं और पीएम मित्र योजना के अंतर्गत दो टेक्सटाइल पार्क सहित सात परियोजनाओं का आकलन किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये परियोजनाएं एकीकृत मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक एवं सामाजिक केंद्रों के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी और इंटर-मॉडल समन्वय के प्रधानमंत्री गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी तथा विभिन्न क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

रेल मंत्रालय

बख्तियारपुर और फतुहा (बिहार) के बीच तीसरी और चौथी लाइन

रेल मंत्रालय ने बिहार के पटना ज़िले में बख्तियारपुर और फतुहा के बीच 24.156 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह खंड किऊल-पटना-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कॉरिडोर (लगभग 390 किलोमीटर) पर एक बहु-ट्रैकिंग पहल का हिस्सा है।

यह परियोजना क्षेत्रीय गतिशीलता, माल ढुलाई क्षमता और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करेगी, जिससे अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट (बाढ़), कैरिज रिपेयर वर्कशॉप (हरनौत) और एसजेवीएन पावर प्लांट (चौसा) सहित प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ ऑटोमोटिव, संगमरमर, पत्थर, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और वस्त्र उद्योग के एसएमई को लाभ होगा।

उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इस रेल लाइन से किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर होगी और पटना, राजगीर, बोधगया, नालंदा तथा बिहार शरीफ के पर्यटन स्थलों तक पर्यटन संपर्क बढ़ेगा। इससे यात्री क्षमता बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगी और बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान मिलेगा।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण, आम जनता से रेल पटरी से दूर रहने की अपील

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के हिम्मतनगर–खेडब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित ब्रॉड गेज लाइन का निरीक्षण 14 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान इस सेक्शन पर तीव्र से ट्रेन चलाई जाएगी। अतः आम नागरिकों से विशेष अपील की जाती है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से रेल पटरी और इसके आसपास के क्षेत्रों से दूर रहें।

परियोजना का चरणबद्ध रूप से कमीशनिंग प्रस्तावित हैः

- हिम्मतनगर से इडर (31 किमी) – वर्तमान चरण में खोलने का लक्ष्य
- इडर से खेड़ब्रह्मा (23.83 किमी) – सितंबर 2025 तक खोलने का लक्ष्य

"यह परिवर्तन केवल गेज में सुधार नहीं है; यह साबरकांठा क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, अवसर और विकास क्षमता में भी सुधार है।"

इस निरीक्षण के पश्चात अंतिम स्वीकृति मिलने पर इस रेल खंड पर नियमित ट्रेन सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। इससे असारवा से खेड़ब्रह्मा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी, जिससे साबरकांठा सहित उत्तर गुजरात के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

इस गेज परिवर्तन परियोजना के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित उत्तर गुजरात के लोगों को अब बेहतर, तेज और सुरक्षित रेल सेवा प्राप्त होगी। इस मार्ग पर उन्नत संरचनाएं और आधुनिक सुरक्षा मानकों को अपनाया गया है, जिससे यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बन सकेगी।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक 19 अगस्त 2025 को होगी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समग्र स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 मई 2025 को एक अलग आयुष परामर्शदात्री समिति का गठन किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय की नवगठित परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक 19 अगस्त 2025 (मंगलवार) को आयोजित होगी। यह बैठक मंत्रालय और सांसदों के बीच सार्थक संवाद को सरल बनाएगी, जिससे आयुष के क्षेत्र में प्रमुख पहलों और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा और परामर्श मुमकिन हो सकेगा। समिति की अध्यक्षता आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव करेंगे।

भारत सरकार ने, भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में आयुष प्रणालियों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, 5 मई 2025 को आयुष मंत्रालय के लिए एक अलग परामर्शदात्री समिति का गठन किया है।

इससे पहले, आयुष मंत्रालय से संबंधित मामलों को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के अधीन देखा जाता था। आयुष के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति का गठन, आयुष संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित, संसदीय निगरानी और सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम संस्थागत कदम है।

आयुष मंत्रालय के लिए स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति का गठन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और समग्र स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री आयुष प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करने और भारत के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के महत्व पर लगातार जोर देते रहे हैं।

यह उपलब्धि आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निरंतर प्रयासों और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समन्वित कार्रवाई का नतीजा है, जिसने इस वर्ष की शुरूआत में समिति को अधिसूचित किया था।

मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण को आगे बढ़ाने और देश भर में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से, समिति के सदस्यों के साथ उपयोगी चर्चा की उम्मीद करता है।

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा कीड्स हट एवं बाल मंदिर के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपीटिशन

'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO), भावनगर मंडल द्वारा संचालित कीड्स हट एवं बाल मंदिर के नन्हें – मुन्हें बच्चों के बीच ड्राइंग कंपीटिशन करवाया गया। सभी प्यारे प्यारे छोटे–छोटे बच्चों ने बहुत हीं सुंदर चित्र बनाए।

यह दोनों स्कूल 37 वर्षों से चलता आ रहा है। इस कंपीटिशन में सभी बच्चों ने बहुत हीं सुंदर चित्र बनाकर वहां उपस्थित पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO),

भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा एवं महिला कल्याण संगठन की सभी पदाधिकारियों का मन मोह लिया। इस दरमियान उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया।

'हर रेल घर तिरंगा' में 18,000 रेल परिवारजन की ऐतिहासिक भागीदारी – महिला कल्याण संगठन अहमदाबाद की अध्यक्षा शेफाली गुप्ता बनीं प्रेरणा स्रोत

अहमदाबाद, 13 अगस्त 2025 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान को एक नई ऊर्जा देते हुए, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, (हफ्हहड) अहमदाबाद की अध्यक्षा श्रीमती शेफाली गुप्ता के नेतृत्व में न्यू रेलवे कॉलोनी, साबरमती में 'हर रेल घर तिरंगा' रैली का भव्य आयोजन हुआ।

इस आयोजन में 2000 से अधिक रेल परिवारजन शामिल हुए। रैली की शुरूआत सामुदायिक भवन, साबरमती से हुई और रेलवे कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए देशभक्ति के रंग में सराबोर वातावरण में 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे गूंजते रहे।

कार्यक्रम में माननीय विधायक डॉ. हर्षदभाई पटेल ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर तिरंगा' आ'ान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है, और रेल परिवार इसका शानदार उदाहरण है।'

श्रीमती शेफाली गुप्ता, जो वर्षों से जनसेवा और सामुदायिक उत्थान में अग्रणी रही हैं, ने कहा — 'हर घर रेल तिरंगा, हर दिल में भारत – यही हमारे देशप्रेम की असली पहचान है।' उनकी प्रेरणा ने इस अभियान को केवल एक रैली नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय एकता के उत्सव में बदल दिया।

रैली के उपरांत 500 से अधिक घरों में कॉलोनीवासियों को तिरंगा वितरित किया गया, ताकि 15 अगस्त को हर घर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराए। अहमदाबाद मंडल द्वारा 14 अगस्त 2025 को मणिनगर और अन्य रेलवे कॉलोनियों में भी यही अभियान जारी रहेगा।

इस साल अहमदाबाद रेल मंडल के 18,000 से अधिक घरों में तिरंगा बाटने का प्लान है। साथ ही अहमदाबाद मंडल के अपने स्टाफ के बीच 'फोटो तिरंगा के साथ' फोटो कम्पटीशन भी रखा है, जिसमे रेलवे मेन को अपना फोटो तिरंगे के साथ खींच कर @ऊम्टऑर्गि को टैग करना है और #ऌं१फ्रं'ॠ१ऌ१ल्लॅ हैशटैग के साथ पोस्ट करना है। डिवीजन अच्छे फोटोग्राफ़्स को अवार्ड भी देगा।

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल ने एक बार फिर साबित किया कि वह देश की प्रगति के साथ–साथ सामाजिक एकजुटता और राष्ट्र निर्माण में भी सदैव अग्रणी है।

भारत में पारदर्शी और उत्तरदायी खाद्य सूचना पत्र लगाने के लिए रूपरेखा तैयार

एफएसएसएआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में भारत में पारदर्शी और उत्तरदायी खाद्य सूचना पत्र लगाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई; खाद्य सूचना पत्र लगाने और विज्ञापन में विश्वास तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया गया

यह परामर्श वर्तमान नियमों की समीक्षा करता है, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करता है और उपभोक्ता संरक्षण, जन स्वास्थ्य तथा खाद्य उद्योग में नवाचार बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों के साथ संरेखण का प्रयास करता है

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उभरते खाद्य क्षेत्र में नैतिक और सही सूचना पत्र तथा विज्ञापन की आवश्यकता पर बल दिया; सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, खाद्य उत्पादों की बारीकी से जाँच करने तथा ऐसे महत्वपूर्ण परामर्श आयोजित करने का आग्रह किया

खाद्य सूचना पत्र केवल एक विपणन उपकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच विश्वास का सबसे आवश्यक कारक भी माना जाना चाहिए, हम खाद्य उत्पाद में शामिल सभी चीजों की सही और ईमानदार घोषणा चाहते हैं और अंतिम निर्णय उपभोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए: श्रीमती निधि खरे

श्री संजीव सान्याल ने विज्ञापनों में वैज्ञानिक दावों के बाहरी सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया; सूचना पत्र उद्योग के लिए अनिश्चितता को कम करने के लिए सूचना पत्र में सभी परिवर्तनों को वर्ष में एक बार लागू करने के एफएसएसएआई के निर्णय की प्रशंसा की

(जीएनएस)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में खाद्य सूचना पत्र, विज्ञापन और दावों पर भारत के नियामक ढांचे को मजबूत करने के एक मजबूत प्रयास के अंतर्गत, 'खाद्य सूचना पत्र, विज्ञापन और दावों पर नियामक ढांचे का व्यापक विश्लेषण' विषय पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस परामर्श में संबंधित मंत्रालयों, सरकारी विभागों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, खाद्य व्यवसायों, राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों, उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 700 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसका उद्देश्य वर्तमान नियमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा खाद्य उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने के स्वरूप तलाशना था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव, श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने उद्घाटन भाषण में खाद्य क्षेत्र में सूचना पत्र और विज्ञापन में नैतिक तथा सत्यनिष्ठ प्रथाओं के महत्व पर बल दिया। श्रीमती श्रीवास्तव ने खाद्य क्षेत्र के विकसित होते माहौल की ओर इशारा करते हुए कहा, "आज चीजें तेजी से बदल रही हैं। अब हम पूरी दुनिया के संपर्क में हैं, जिसका अर्थ है कि हमें कई सकारात्मक बदलावों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना होगा, साथ ही खाद्य उत्पादों की और भी बारीकी से जाँच करनी होगी। इस तेजी से बदलती दुनिया में, इस तरह के परामर्श अत्यंत आवश्यक हैं।"

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने खाद्य उद्योग में ईमानदार और सत्य घोषणाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उद्योग से सच्ची और ईमानदार घोषणाएँ करने, स्वेच्छा से यह बताने कि उत्पाद में क्या है और भ्रामक विज्ञापनों और छल–कपट से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "खाद्य सूचना पत्र केवल एक विपणन उपकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे निमार्ता और उपभोक्ता के बीच विश्वास का सबसे आवश्यक कारक भी माना जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि खाद्य उत्पाद में जो कुछ भी शामिल है, उसकी सच्ची और ईमानदार घोषणा हो और अंतिम निर्णय उपभोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।" उन्होंने यह सुनिश्चित करने के सामूहिक दायित्व पर भी बल दिया कि यह जानकारी सटीक, पारदर्शी और सत्य हो, ताकि उपभोक्ता पूर्ण विश्वास के साथ सूचित, सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प चुन सकें।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, श्री संजीव सान्याल ने उद्घाटन सत्र के दौरान अपने विशेष संबोधन में कहा, 'विज्ञापनों में दावों के मुद्दे की भी गहन जाँच की आवश्यकता है क्योंकि भले ही उनके समर्थन में कथित वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हों, फिर भी उन्हें बाहरी रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है।' इस संबंध में श्री सान्याल ने एफएसएसएआई के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा, 'इस वर्ष की शुरूआत में एफएसएसएआई द्वारा एक घोषणा की गई थी कि सभी सूचना पत्र में परिवर्तन और संबंधित नियम तथा विनियम अब वर्ष में केवल एक बार, 1 जुलाई को लागू होंगे। यह वास्तव में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सूचना पत्र उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या और अनिश्चितता को दूर करता है।'

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री प्रभात ने खाद्य क्षेत्र में झूठे दावों की गंभीरता का उल्लेख करते हुए, उत्तरदायित्व और सटीक संचार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि विज्ञापन नैतिक, सत्य और भ्रामक न हों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दावों के संदर्भ में। इस क्षेत्र में झूठे दावे न केवल उपभोक्ता के भरोसे को कमजोर करते हैं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा भी पैदा करते हैं।"

आईबीसी 22 अगस्त 2025 को युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीवाईबीएस) आयोजित करेगा

(जीएनएस)।

धम्म का सार संरक्षित करने में युवाओं की भूमिका को मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी), नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025 को युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीवाईबीएस) आयोजित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के नालंदा हॉल में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

आईसीवाईबीएस ने अपने पिछले सम्मेलनों में जीवंत विषयों पर गहन चर्चा की है। 2023 में "बौद्ध तीर्थयात्रा" पर चर्चा से लेकर 2024 में "शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में बुद्ध धम्म" पर जोर देने तक, 2025 की विषय वस्तु का उद्देश्य "21वीं सदी में बुद्ध धम्म में ज्ञान संचार" पर चर्चा करना है।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह उपस्थित रहेंगे। मुख्य भाषण प्रख्यात बौद्ध इतिहासकार प्रो. केटीएस सराओ देंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की भूमिका को बार–बार "धम्म सेतु" के रूप में देखा है, जो एक आध्यात्मिक सेतु है जो न केवल बौद्ध–बहुल देशों को बल्कि पूरे विश्व को जोड़ता है। भारत को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन और पाली को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने जैसी पहलों के माध्यम से बुद्ध धम्म के संरक्षण में योगदान देने में अग्रणी होने पर गर्व है। "धम्म–आधारित सद्भाव" का सिद्धांत भारत के पंचामृत सिद्धांत में निहित पाँच स्तंभों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

इसलिए, यह सम्मेलन

निम्नलिखित पर गहन शोध करेगाः

धम्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने करुणा, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव पर आधारित समावेशिता के सिद्धांत पर आधारित एक विरासत छोड़ी है। पूरे भारत में प्रसारित अपने शिलालेखों के माध्यम से भावी पीढ़ियों को तैयार करने में सम्राट अशोक के प्रयासों के सम्मान में, इस संगोष्ठी का पहला विषय "बुद्ध धम्म के प्रसार में अशोक की भूमिका" पर चर्चा करना है। यह विषय वस्‍तु उनकी शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन करती है, जो श्रीलंका से हेलेनिस्टिक क्षेत्रों और मध्य एशिया तक फैली।

भारतीय परंपरा "गुरु–शिष्य" संबंध के महत्व के लिए जानी जाती है, जो ज्ञान हस्तांतरण का आधार है। दूसरा विषय "गुरु शिष्य परंपरा – बुद्ध धम्म में ज्ञान हस्तांतरण के मॉडल" पर चर्चा करेगा। गुरु केवल धम्म की व्याख्या ही नहीं करते, बल्कि अपने आचरण और जीवनशैली में परिलक्षित वास्तविक अभ्यासों के माध्यम से उसे साकार भी करते हैं। शिष्य केवल धम्म का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि उनकी भूमिका अध्ययन से भी आगे तक जाती है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के वाहक होते हैं। इसलिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है जिस पर आगे बढ़ना आवश्यक है।

बौद्ध धर्म आधुनिक तकनीक के साथ–साथ विकसित हो रहा है और अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए नए साधनों को अपना रहा है। जैसे–जैसे युवा पीढ़ी डिजिटल नवाचार की ओर आकर्षित हो रही है, वे धम्म से जुड़े रहने और उसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम हैं। भारत में, केवल 30 प्रतिशत महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करना जानती हैं, जबकि पुरुषों में यह दर 57 प्रतिशत है, जो डिजिटल माध्यम से लैंगिक अंतर को पाटने की तत्काल आवश्यकता को दशार्ता है। डिजिटल पहुँच में इस लैंगिक अंतर और डिजिटल माध्यम से ज्ञान के प्रसार की चुनौतियों का समाधान करते हुए, तीसरा विषय "डिजिटल युग में लैंगिक और पहुँच के संदर्भ में ज्ञान संचरण" पर जोर देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाषा–समावेशी बौद्ध संसाधनों, मोबाइल माइंडफुलनेस ऐप्स और वर्चुअल रिट्रीट जैसे नवाचारों के माध्यम से, बुद्ध की आध्यात्मिक शिक्षाओं के संरक्षण की चुनौतियों का समाधान करती है।

अंतिम विषय वस्तु में समकालीन आवश्यकताओं के लिए ऐतिहासिक ज्ञान को जोड़ने और शिक्षाओं को सुलभ बनाने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। शैक्षणिक संस्थान इन शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता बनाए रखने में प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, अंतिम विषय "ज्ञान के संरक्षक के रूप में बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों और संघ की स्थितिः भविष्य के लिए सामुदायिक शिक्षा और संरक्षण" पर प्रकाश डालेगा।

भारत भर के युवा प्रतिभाओं का एक उत्कृष्ट समूह उपरोक्त विषय पर प्रस्तुति देने के लिए एक साथ आ रहा है। इसलिए, तीसरा आईसीवाईबीएस, धम्म संरक्षकों की अगली पीढ़ी के पोषण और समकालीन संदर्भों में बुद्ध धम्म के शाश्वत मूल्यों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। अशोक की विरासत, गुरु–शिष्य परंपरा के ज्ञान, डिजिटल युग में समावेशिता की आवश्यकता और शैक्षणिक एवं मठीय संस्थानों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बौद्ध ज्ञान का प्रसार 21वीं सदी और उसके बाद भी जीवंत, सुलभ और प्रासंगिक बना रहे।

वियतनाम, रूस, कंबोडिया और म्यांमार जैसे कई देशों के विद्वान, जो भारत में रहते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, तथा बौद्ध अध्ययन पृष्ठभूमि वाले युवा शिक्षाविदों द्वारा शोधपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

आईजीएनसीए ने अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देते हुए पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया

आईजीएनसीए ने भारत के विज्ञान और संस्कृति के एकीकृत मंच के उपलक्ष्य में बीएसआईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त ट्रस्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी), लखनऊ के साथ आईजीएनसीए, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित ग्यारह पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. महेश जी. ठक्कर थे। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, डीन (अकादमिक) प्रो. प्रतापानंद झा, अकादमिक इकाई के प्रभारी प्रो. अरुण भारद्वाज और संबंधित प्रभागों के अन्य प्रमुख और डीन भी उपस्थित थे।

यह समझौता ज्ञापन देश में विज्ञान और संस्कृति को एक एकीकृत मंच पर लाने की अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य देश की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर, आईजीएनसीए द्वारा संचालित ग्यारह पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक सूचना विज्ञान से लेकर भारतीय साहित्य तक के क्षेत्र शामिल

थे। इसका उद्देश्य समकालीन शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना था। कुशल पेशेवरों को विकसित करने के लिए तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। इससे शिक्षार्थियों, विशेषज्ञों और जीवंत परंपराओं के बीच सार्थक आदान–प्रदान को बढ़ावा मिलता है।

डॉ. सच्चिदानंद जोशी और प्रो. महेश जी. ठक्कर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईजीएनसीए के संरक्षण प्रभाग के प्रमुख एवं प्रोफेसर डॉ. अचल पंड्या और बीएसआईपी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शिल्पा पांडे इस सहयोग के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगी। आईजीएनसीए और बीएसआईपी के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतःविषय अनुसंधान, संयुक्त आयोजनों और साझा विशेषज्ञता के माध्यम से विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करना है। यह डिजिटलीकरण, शिक्षा और समुद्री इतिहास में जलवायु परिवर्तन पर प्रोजेक्ट मौसम के समर्थन पर केंद्रित है। सहयोग में अनुसंधान, प्रलेखन, संरक्षण, संग्रहालय विकास, क्षेत्रीय कार्य, दृश्य–श्रव्य अभिलेख, संयुक्त प्रकाशन, और संरक्षण एवं विरासत प्रबंधन में प्रशिक्षण के साथ–साथ जन–पहुंच शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की विरासत को संरक्षित, व्याख्यायित और प्रस्तुत करना है।

इस अवसर पर, प्रो. महेश जी. खट्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और बीएसआईपी के बीच सहयोग विज्ञान, कला और संस्कृति को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी प्रेरित होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल हमारे इतिहास और विरासत को समझने के लिए है, बल्कि भविष्य के लिए उनके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने आगे बताया कि यह विज्ञान, कला और संस्कृति को एक मंच पर लाने के लिए आईजीएनसीए के साथ एक संयुक्त प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में और अधिक प्रदर्शनियां, शोध और प्रकाशन किए जाने और लोगों को पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जागरूक करने के लिए ही आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने 'भारत स्टील' का लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया। इस अवसर पर इस्पात सचिव श्री संदीप पौंड्रिक और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह शुभारंभ द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए आयोजित एक कार्यशाला के दौरान हुआ। इसने संपूर्ण इस्पात मूल्य श्रृंखला में विकास, नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत स्टील, इस्पात मंत्रालय का इस्पात इकोसिस्टम का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी है।

16-17 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों, नीति निमार्ताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और निवेशकों को भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करने, हरित और टिकाऊ इस्पात निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसरों की खोज करने के लिए एक साथ लाएगा।

इस आयोजन में विषयगत सत्र, क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन, राज्य और राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन, सीईओ सम्मेलन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियाँ, क्रेता-विक्रेता बैठकें और प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी शामिल होगी। भारत और उसके बाहर सबसे बड़ी इस्पात प्रदर्शनी बनने के अपने दृष्टिकोण के साथ, भारत स्टील का लक्ष्य भारत को वैश्विक इस्पात उद्योग में नवाचार, सहयोग और निवेश का केंद्र बनाना है।

मुख्यमंत्री ने एच5 एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के सम्भावित खतरे के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए

संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं : मुख्यमंत्री

प्रदेश के सभी प्राणि उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया जाए

सभी कर्मचारियों को एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए

समय पर समन्वित एवं सख्त कार्रवाई बर्ड फ्लू के सम्भावित संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करेगी

लखनऊ : (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां एच 5 एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के सम्भावित खतरे के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के सभी प्राणि उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी प्राणि उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉर्चिंग की प्रक्रिया भी अपनायी जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए। कर्मचारियों को पी0पी0ई0 किट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए तथा पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरन्तर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ल5 एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

210 पंचायत प्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एआई संचालित टूल "सभासार" का शुभारंभ होगा तथा पंचायत प्रतिनिधिओं को सम्मानित किया जाएगा

(जीएनएस)।

पंचायती राज मंत्रालय 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 210 पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में मेजबानी करेगा। अपने जीवनसाथी और नोडल अधिकारियों के साथ, कुल 425 प्रतिभागी इस समारोह में शामिल होंगे।

इन विशिष्ट अतिथियों के लिए 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर

पर उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय "आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत की पहचान" है, जो विकसित भारत के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में आत्मनिर्भर पंचायतों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस सम्मान समारोह के दौरान एआई संचालित 'सभासार' एप्लिकेशन का शुभारंभ होगा और 'ग्रामोदय संकल्प पत्रिका' के 16वें अंक का भी विमोचन होगा।

इस वर्ष के विशेष अतिथियों में बड़ी संख्या में महिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी सामुदायिक पहल जैसे प्रत्यक्ष सुधार लाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ग्रामीण नेतृत्व की उभरती हुई शक्ति का उदाहरण हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शासन संबंधी ज़िम्मेदारियों को दूरदर्शी विकास दृष्टिकोणों के साथ सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। इन्होंने हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मिशन इंद्रधनुष जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं को साकार कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और साथ ही जमीनी स्तर पर नवीन स्थानीय पहलों व समाधानों को प्रोत्साहित भी किया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 1.47 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी, स्वीकृत घरों की कुल संख्या 8.56 लाख हुई

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

सभी के लिए आवास' (एचएफए) के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 1.47 लाख अतिरिक्त पक्के मकानों को मंजूरी दी है। इस नवीनतम मंजूरी के साथ, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 8.56 लाख हो गई है। यह निर्णय 12 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित जीपीओए-2 में श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की चौथी बैठक के दौरान लिया गया। कस्तूरबा गांधी मार्ग कार्यालय में आयोजित यह सभी के लिए आवास (एचएफए) प्रभाग की पहली बैठक थी।

बैठक में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (संयुक्त परामर्श एवं प्रबंध निदेशक) श्री कुलदीप नारायण, आवास वित्त मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएमएवाई-यू मिशन निदेशक और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल 1,46,582 घरों को मंजूरी दी गई है।

स्वीकृत आवास, शहरी गरीबों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से युक्त किफायती और सम्मानजनक पक्के मकान उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। यह निर्णय शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है।

बैठक को संबोधित करते हुए, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवास परियोजनाओं को बुनियादी ढांचे के गलियारे के साथ जोड़ने पर जोर देने का आग्रह किया।

भारत ने एएलएमएम के अंतर्गत 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की

एएलएमएम के अंतर्गत सौर पीवी निर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यह 2014 में 2.3 गीगावाट से अब 100 गीगावाट हो गई है: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

(जीएनएस)।

भारत ने सौर पीवी मॉड्यूल के लिए स्वीकृत मॉडल और निमार्ताओं की सूची (एएलएमएम) में शामिल 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त कर ली है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में परिवर्तन की वैश्विक अनिवार्यता के अनुरूप, एक मजबूत और आत्मनिर्भर सौर विनिर्माण इकोसिस्टम के निर्माण में देश की तीव्र प्रगति को दर्शाती है।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इस उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा, "भारत ने अनुमोदित मॉडल और निमार्ताओं की सूची (एएलएमएम) के अंतर्गत 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता - एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह वर्ष 2014 में केवल 2.3 गीगावाट थी, और यह उल्लेखनीय वृद्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी परिवर्तनकारी पहलों से प्रेरित होकर, हम एक मजबूत, आत्मनिर्भर सौर विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर हमारे मार्ग को मजबूत करती है।"

भारत सरकार की प्रतिबद्धता भारत को सौर पीवी विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करना है। इन हस्तक्षेपों के उत्प्रेरक प्रभाव के परिणामस्वरूप सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता में विस्तार हुआ है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.3 गीगावाट से बढ़कर आज 100 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और वैश्विक डीकाबोर्नाइजेशन प्रयासों में सार्थक योगदान देता है।

एएलएमएम आदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 02 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पहली एएलएमएम सूची 10 मार्च 2021 को लगभग 8.2 गीगावाट की प्रारंभिक सूचीबद्ध क्षमता के साथ प्रकाशित की गई थी। केवल चार वर्षों में, यह क्षमता बारह गुना से अधिक बढ़कर 100 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। यह उल्लेखनीय विस्तार केवल प्राप्त क्षमता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निमार्ताओं की संख्या की व्यापकता से भी जुड़ा है, जो वर्ष 2021 में 21 से बढ़कर 100 निमार्ता हो गए हैं, जो वर्तमान में 123 विनिर्माण इकाइयाँ संचालित कर रहे हैं।

इस वृद्धि में स्थापित कंपनियों और नए प्रवेशकों, दोनों का योगदान शामिल है, जिनमें से कई कंपनियों ने उच्च-दक्षता वाली तकनीकों और ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत परिचालनों को अपनाया है। इसका परिणाम एक विविध और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण परिदृश्य है जो घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और वैश्विक बाजारों की सेवा करने में सक्षम है।

एसपीआरईई 2025 का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार

उप-क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम ने ईएसआईसी की एसपीआरईई 2025 पहल पर जागरूकता अभियान चलाया

(जीएनएस)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा शुरू की गई "नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन स्कीम (एसपीआरईई 2025)" एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस स्कीम का शुभारंभ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने किया और यह 1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी। एसपीआरईई 2025 के तहत, अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों, जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं, को निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग का सामना किए बिना पंजीकरण कराने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया जाता है।

इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु, ईएसआईसी उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा गुरुग्राम औद्योगिक संघ परिसर में एक संगोष्ठी एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कार्यालय प्रमुख श्री सुनील यादव, निदेशक (प्रभारी) ने नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को एसपीआरईई 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गुरुग्राम औद्योगिक संघ के अध्यक्ष श्री जे.एन. मंगला, गुड़गांव उद्योग संघ के श्री सुमित राव, गुरुग्राम औद्योगिक संघ के महासचिव श्री संजीव बंसल एवं 60 से अधिक अन्य नियोक्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।

संगोष्ठी के अतिरिक्त, एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें सीमा कपूर, सुनील, विनीता, अंकुर कोहली, शुभम एवं सुनील ने प्रतिभागियों को उपरोक्त योजना के अंतर्गत ईएसआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली पंजीकरण सुविधाओं, अन्य लाभों एवं चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। इस नाटक के माध्यम से ईएसआईसी योजनाओं और बीमारी में मिलने वाले लाभ, चिकित्सा लाभ, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ और आश्रित लाभ के साथ-साथ ईएसआईसी अस्पतालों और पैनल अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रसारित की गई।

एमएसडीई ने ओडिशा में राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत और आधुनिक बनाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में ओडिशा सरकार के कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से कल भुवनेश्वर के विश्व कौशल केंद्र में राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन स्कीम पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला में आईटीआई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना के विजन, संरचना और प्रचालनगत ढांचे पर चर्चा की गई तथा उभरती कार्यबल आवश्यकताओं के साथ संयोजन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र और प्रशिक्षण संस्थानों से उनके विचार एकत्रित किए गए।

एमएसडीई के सचिव श्री रजित पुन्हानी ने उच्च-गुणवत्तापूर्ण, बाजार-संगत कौशल के माध्यम से भारत के युवाओं को सशक्त बनाने में इस योजना की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, "राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन स्कीम केवल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के बारे में नहीं, यह भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के मूल स्वरूप को पुनर्जीवित करने के बारे में है। हब-एंड-स्पोक मॉडल, उद्योग-आधारित शासन और वैश्विक-मानक प्रशिक्षण के माध्यम से, हमारा लक्ष्य आईटीआई को नवोन्मेषण, रोजगारपरकता और उद्यमिता का केंद्र बनाना है। अपने मजबूत औद्योगिक आधार और नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के साथ, ओडिशा इस बदलाव का नेतृत्व करने और देश के बाकी हिस्सों को प्रेरित करने की अनूठी स्थिति में है। यह केवल युवाओं को वर्तमान में रोजगार के लिए तैयार करने से संबंधित नहीं है—यह उन्हें भविष्य की अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है।"

कार्यशाला में ओडिशा की आईटीआई यात्रा पर एक गहन प्रस्तुति दी गई, जिसमें तकनीकी शिक्षा, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और उद्योग साझेदारी में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

इसमें राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ओडिशा के दृष्टिकोण, तत्परता और कार्यनीतिक योजनाओं को रेखांकित किया गया, जिससे राज्य आधुनिक कौशल विकास में अग्रणी बन सके।

इसके अतिरिक्त, उद्योग प्रतिनिधियों ने आईटीआई प्रशिक्षण को भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर अपने विचार साझा किए, जबकि तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों और संकाय सदस्यों ने जमीनी स्तर के दृष्टिकोण, बहुमूल्य जानकारी और सुझाव प्रदान किए। प्रमुख अनुशंसाएं वैश्विक मानकों और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम उन्नयन, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)-आधारित मॉडल के लिए मार्गदर्शन सहायता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की पहल को बढ़ावा देने, हाइब्रिड

ईपीएफओ के पीडीयूएनएएसएस ने सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कम्पैशन के सहयोग से 'शासन में करुणा' पर प्रशिक्षण का आयोजन किया

(जीएनएस)।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कम्पैशन (एसएमजीसी) के सहयोग से "शासन में करुणा" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोक सेवकों को सेवा वितरण में सहानुभूति और दक्षता का समन्वय करने हेतु कौशल और मानसिकता से लैस करना है।

कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:00 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी के मंथन हॉल में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्थान के निदेशक श्री कुमार रोहित, सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कम्पैशन के विशेषज्ञ और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 60 से अधिक प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि 100 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

पीडीयूएनएएसएस की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला के 17वें संस्करण, "री-इमेजिनिंग गवर्नेंस डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस (आरजीडीई)" के दौरान, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने "रीइमेजिनिंग कम्पैशनेट गवर्नेंस" विषय पर मुख्य

भाषण दिया था । इसी कार्यक्रम में, ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति ने ईपीएफओ के अधिकारियों से अपने दैनिक कर्तव्यों के निर्वहन में करुणा का अभ्यास करने का आग्रह किया था। इसी पहल के तहत, पीडीयूएनएएसएस ने शासन में करुणा पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने की पहल की। एक पायलट परियोजना के रूप में, इसने अपने परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए शासन में करुणा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एसएमजीसी के साथ सहयोग किया।

अपने स्वागत भाषण में, पीडीयूएनएएसएस के निदेशक, श्री कुमार रोहित ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शासन का सार केवल कानूनों के क्रियान्वयन में ही नहीं, बल्कि उन लोगों को समझने में भी निहित है जिनकी वे सेवा करते हैं। उन्होंने कहा, "प्रक्रियाएं करुणा से निर्देशित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शासन वास्तव में नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो।"

सुश्री दीक्षा चोपड़ा, सुश्री इशानी सचदेवा, श्री शिव कुमार शर्मा, सुश्री जहांआरा राबिया रजा और सुश्री इकांशी खन्ना के नेतृत्व में एसएमजीसी के संकाय सदस्यों ने सहानुभूति और करुणा के बीच अंतर, सोच-समझकर निर्णय लेना, सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति के साथ संघर्ष समाधान जैसे विषयों पर आकर्षक सत्र आयोजित किए। प्रशिक्षण में केस स्टडी, रोल-प्ले अभ्यास और चिंतनशील चर्चाएं शामिल थीं, जिससे प्रतिभागियों को अपने दैनिक कार्यों में करुणा को शामिल करने के व्यावहारिक तरीकों की पहचान करने में मदद मिली।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का संचालन करेगा

देश भर में 1850 से अधिक जिलों/शहरों/कस्बों में शिविर आयोजित किए जाएंगे

चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान

2 करोड़ डीएलसी प्राप्त करने के लिए परिपूर्णता मॉडल अपनाया गया

(जीएनएस)।

पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। नवंबर, 2024 में 845 शहरों में आयोजित डीएलसी अभियान 3.0 में 1.62 करोड़ डीएलसी जमा किए गए थे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) अब चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित करेगा, जो 1 से 30 नवंबर, 2025 तक भारत भर में 1850 से अधिक जिलों/शहरों/कस्बों (2500 शिविर स्थानों) में आयोजित किया जाएगा। विभाग ने 30 जुलाई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अभियान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।